



आधुनिक समाचार

आधुनिक भारत का आधुनिक नजरिया

प्रयागराज से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

वर्ष -11 अंक -164

प्रयागराज, बुधवार 17 सितम्बर, 2025

पृष्ठ- 8

मूल्य : 3.00 रुपये

राजनीतिक दलों को POSH एक्ट में नहीं ला सकते, किस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों दफ्तर नहीं हैं, इसलिए POSH एक्ट (Sexual Harassment of Women at Workplace Act) इन पर लागू नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि आगर ऐसा हुआ तो लैकमेलिंग के दरवाजे खुल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्तीर्ण (रोपीड़न, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में लाने की मांग गली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता योगमाया जी. की ओर से वरिष्ठ अधिकारी शोभा गुप्ता ने सीजेआई बीए गवर्नर, जस्टिस ए. एस. चंद्रुकर की पीठ को बताया कि हालांकि कई महिलाएं राजनीतिक दलों की सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन केवल सीजेएपी ने ही बाहरी सदस्यों वाली एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन किया है। इससे राजनीतिक दलों में महिलाओं के पास योन उत्तीर्ण के खिलाफ कई उम्मीदें बचता। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अपनी कमिटी के बारे में जानकारी



की अपर्याप्तता को स्वीकार किया है। उन्होंने मांग की है कि यह कानून रजिस्टर्ड पार्टियों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए, जो संविधान में राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा रखती है। इसमें सुनिक्षित वर्क लेस सहित महिलाओं की गरिमा की रक्षा का प्रवाधन है। हालांकि, मर्यादा न्यायाधीश की अधिकारी वाली पीठ ने पुछा कि आप राजनीतिक दलों को दफ्तर (वर्कलेस) के बराबर कैसे मान सकते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी रिट याचिका पर विचार करने से नहीं देता। इसमें शामिल होते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून में राजनीतिक दल कैसे शामिल हो सकते हैं? केरल हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को इष्टण अधिनियम के अधीन करना भानुमत की पिटारा खोल देगा और लैकमेल का एक साधन बन जाएगा। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने योगमाया की एक रिट याचिका पर विचार करने से नहीं है।

इनकार कर दिया था और उन्हें चुनाव आयोग और अन्य प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कतर पर हमले के लिए इजरायल की कहा कि जनहित याचिका दायर करने वाली याचिकाकर्ता द्वारा राजनीतिक दलों को नियोक्ता और कार्यकारी सदस्यों को कर्मचारी मानने के उद्दरण शायद उपयुक्त न हो। हालांकि, बैचं इस बात से सहमत थी कि यह जरूरी मुद्दा है और इस पर चुनाव आयोग को फैसला करना चाहिए। चुनाव आयोग ही राजनीतिक पार्टियों को रजिस्टर करता है और उनके वोट शेरर के हिसाब से उन्हें राष्ट्रीय का आर्य स्तर की पार्टी का नियोक्ता करता है। दिलवस्य बात यह है कि मार्च 2022 में, केरल हाईकोर्ट के एक फैसले सुनाया था कि राजनीतिक दलों में कर्मचारी-नियोक्ता संबंध न होने की स्थिति में, 2013 के कार्यस्थल पर महिलाओं के बाबत राजनीतिक दलों को एक साधन बन जाएगा। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने योगमाया की एक रिट याचिका पर विचार करने से नहीं है।

बिहार चुनाव में एनडीए दिखाएगा एकजुटता, पहली बार बीजेपी-जेडीयू जारी करेंगे जॉड्इंट मेनिफेस्टो

पटना। बिहार विधानसभा

चुनाव 2025 से पहले एनडीए



एकजुटता का मजबूत संदेश देने की तैयारी में है। बृथ स्तर पर संयुक्त कार्यक्रमों और विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलनों के बाद अब एनडीए ने साझा घोषणापत्र जारी करने का प्लान बनाया है। सूत्रों के अनुसार, बीजेपी और जनता दल (यूनाइटेड) मिलकर अगले पांच साल के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का रोडमॉड एक ही दस्तावेज में प्रस्तुत करेंगे। 2020 के चुनाव में बीजेपी और

अलग घोषणापत्र पेश किए थे। बीजेपी ने 22 अक्टूबर 2020 को संकल्प पत्र जारी कर मुफ्त कोविड टीकाकरण, 19 लाख रोजगार, महिलाओं को 33फीसदी आरक्षण और 5 लाख करोड़ के निवेश कार्यक्रमों और जनता दल (यूनाइटेड) मिलकर अगले पांच साल के लिए नीतीश कुमार के जेडीयू ने 'सात निश्चय योजना पार्ट-2' का घोषणापत्र पेश किया, जिसमें पार्टी, साकृ, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जो था इस बार

रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। बीजेपी के निवेश कार्यक्रमों और विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलनों के बाद अब एनडीए ने साझा घोषणापत्र जारी करने का प्लान बनाया है। सूत्रों के अनुसार, बीजेपी और जनता दल (यूनाइटेड) मिलकर अगले पांच साल के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का रोडमॉड एक ही दस्तावेज में प्रस्तुत करेंगे। 2020 के चुनाव में बीजेपी और

अलग घोषणापत्र पेश किए थे। बीजेपी ने 22 अक्टूबर 2020 को संकल्प पत्र जारी कर मुफ्त कोविड टीकाकरण, 19 लाख रोजगार, महिलाओं को 33फीसदी आरक्षण और 5 लाख करोड़ के निवेश कार्यक्रमों और जनता दल (यूनाइटेड) मिलकर अगले पांच साल के लिए नीतीश कुमार के जेडीयू ने 'सात निश्चय योजना पार्ट-2' का घोषणापत्र पेश किया, जिसमें पार्टी, साकृ, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जो था इस बार

एक ही दस्तावेज में प्रस्तुत करेंगे। 2020 के चुनाव में बीजेपी और

अलग घोषणापत्र पेश किए थे। बीजेपी ने 22 अक्टूबर 2020 को संकल्प पत्र जारी कर मुफ्त कोविड टीकाकरण, 19 लाख रोजगार, महिलाओं को 33फीसदी आरक्षण और 5 लाख करोड़ के निवेश कार्यक्रमों और जनता दल (यूनाइटेड) मिलकर अगले पांच साल के लिए नीतीश कुमार के जेडीयू ने 'सात निश्चय योजना पार्ट-2' का घोषणापत्र पेश किया, जिसमें पार्टी, साकृ, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जो था इस बार

एक ही दस्तावेज में प्रस्तुत करेंगे। 2020 के चुनाव में बीजेपी और

अलग घोषणापत्र पेश किए थे। बीजेपी ने 22 अक्टूबर 2020 को संकल्प पत्र जारी कर मुफ्त कोविड टीकाकरण, 19 लाख रोजगार, महिलाओं को 33फीसदी आरक्षण और 5 लाख करोड़ के निवेश कार्यक्रमों और जनता दल (यूनाइटेड) मिलकर अगले पांच साल के लिए नीतीश कुमार के जेडीयू ने 'सात निश्चय योजना पार्ट-2' का घोषणापत्र पेश किया, जिसमें पार्टी, साकृ, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जो था इस बार

एक ही दस्तावेज में प्रस्तुत करेंगे। 2020 के चुनाव में बीजेपी और

अलग घोषणापत्र पेश किए थे। बीजेपी ने 22 अक्टूबर 2020 को संकल्प पत्र जारी कर मुफ्त कोविड टीकाकरण, 19 लाख रोजगार, महिलाओं को 33फीसदी आरक्षण और 5 लाख करोड़ के निवेश कार्यक्रमों और जनता दल (यूनाइटेड) मिलकर अगले पांच साल के लिए नीतीश कुमार के जेडीयू ने 'सात निश्चय योजना पार्ट-2' का घोषणापत्र पेश किया, जिसमें पार्टी, साकृ, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जो था इस बार

एक ही दस्तावेज में प्रस्तुत करेंगे। 2020 के चुनाव में बीजेपी और

अलग घोषणापत्र पेश किए थे। बीजेपी ने 22 अक्टूबर 2020 को संकल्प पत्र जारी कर मुफ्त कोविड टीकाकरण, 19 लाख रोजगार, महिलाओं को 33फीसदी आरक्षण और 5 लाख करोड़ के निवेश कार्यक्रमों और जनता दल (यूनाइटेड) मिलकर अगले पांच साल के लिए नीतीश कुमार के जेडीयू ने 'सात निश्चय योजना पार्ट-2' का घोषणापत्र पेश किया, जिसमें पार्टी, साकृ, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जो था इस बार

एक ही दस्तावेज में प्रस्तुत करेंगे। 2020 के चुनाव में बीजेपी और

अलग घोषणापत्र पेश किए थे। बीजेपी ने 22 अक्टूबर 2020 को संकल्प पत्र जारी कर मुफ्त कोविड टीकाकरण, 19 लाख रोजगार, महिलाओं को 33फीसदी आरक्षण और 5 लाख करोड़ के निवेश कार्यक्रमों और जनता दल (यूनाइटेड) मिलकर अगले पांच साल के लिए नीतीश कुमार के जेडीयू ने 'सात निश्चय योजना पार्ट-2' का घोषणापत्र पेश किया, जिसमें पार्टी, साकृ, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जो था इस बार

एक ही दस्तावेज में प्रस्तुत करेंगे। 2020 के चुनाव में बीजेपी और

अलग घोषणापत्र पेश किए थे। बीजेपी ने 22 अक्टूबर 2020 को संकल्प पत्र जारी कर मुफ्त कोविड टीकाकरण, 19 लाख रोजगार, महिलाओं को 33फीसदी आरक्षण और 5 लाख करोड़ के निवेश कार्यक्रमों और जनता दल (यूनाइटेड) मिलकर अगले पांच साल के लिए नीतीश कुमार के जेडीयू ने 'सात निश्चय योजना पार्ट-2' का घोषणापत्र पेश किया, जिसमें पार्टी, साकृ, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जो था इस बार

एक ही दस्तावेज में प्रस्तुत करेंगे। 2020 के चुनाव में बीजेपी और

अलग घोषणापत्र पेश किए थे। बीजेपी ने 22 अक्टूबर 2020 को संकल्प पत्र जारी कर मुफ्त कोविड

